सिविल विविध

माननिए न्यायमूर्ति डी. एस. तेवतिया और पी. एस. पट्टर के समक्ष

करण सिंह, आदि, - याचिकाकर्ता.

बनाम

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र से रजिस्ट्रार और अन्य, - उत्तरदाता.

1975 की सिविल रिट याचिका संख्या 4751।

24 सितंबर, 1975.*भारत का संविधान* - अनुच्छेद *29 (2) और* 226 - *राज्य सहायता प्राप्त करने वाले निजी कॉलेज - छात्र - क्या उन्हें उसमें प्रवेश लेने का अधिकार है - रिट याचिका - क्या ऐसे कॉलेज के खिलाफ सक्षम है - कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम* (1956 *का बारहवीं)* धारा *4 (ए)* और (*के)* - अनुसूची I संविधि *4* (iv*)* (*1974* का अध्यादेश XXI - *खंड* 22 - *विश्वविद्यालय - क्या उसके पास उससे संबद्ध निजी कॉलेज के प्रिंसिपल को नियुक्त करने की शक्ति है - दंड प्रक्रिया संहिता* (1973) - *धारा* 144 - *कॉलेज के प्रबंधन के बारे में विवाद - जिला मजिस्ट्रेट - क्या ऐसे कॉलेज को चलाने के लिए एक प्रशासक नियुक्त कर सकता है।.*

अभिनिर्धारित *:*

भारत के संविधान 1958 के अनुच्छेद 29 के खंड (2) के मद्देनजर, छात्रों को राज्य निधि यों से सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षिक संस्थान में प्रवेश के लिए विचार किए जाने का मौलिक अधिकार है।

(पैरा 12)

अभिनिर्धारित *:*

संविधान के अनुच्छेद 29 का खंड (2) छात्र को राज्य-सहायता प्राप्त संस्थान में भी प्रवेश के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदान करता है और, एक आवश्यक निहितार्थ द्वारा, यह ऐसे राज्य-सहायता प्राप्त संस्थान पर एक समान कर्तव्य डालता है कि वह प्रवेश के लिए आवेदक के दावे पर विचार करने से इनकार न करे। अधिकार प्रदान करने में उस व्यक्ति पर तदनुरूपी कर्तव्य डालने की परिकल्पना की गई है जिसके विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है और जब ऐसा व्यक्ति अवैध रूप से ऐसे व्यक्ति के अधिकार से इनकार करता है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय ऐसे व्यक्ति को रिट जारी करने के लिए सक्षम है, भले ही वह व्यक्ति एक निजी व्यक्ति हो। यह तय करने में यह देखा

जाना चाहिए कि क्या कोई रिट किसी प्राधिकारी या व्यक्ति के खिलाफ सक्षम है कि क्या कानून उस व्यक्ति पर दायित्व डालता है और याचिकाकर्ता पर संबंधित अधिकार डालता है। यदि कानून किसी निजी व्यक्ति पर इस तरह का दायित्व डालता है और यदि ऐसा निजी व्यक्ति उस दायित्व को पूरा करने में अवैध रूप से कार्य करता है या अवैध रूप से उस दायित्व को पूरा करने से इनकार करता है, तो ऐसे निजी व्यक्ति को भी रिट जारी की जा सकती है।

(पैरा 14).

अभिनिर्धारित *:*

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 की धारा 4 विश्वविद्यालय द्वारा की जा सकने वाली गतिविधि के दायरे को इंगित करती है। सीखने की उन्नति और ज्ञान का प्रसार निस्संदेह किसी भी विश्वविद्यालय का मूल उद्देश्य है, लेकिन शक्ति या कर्तव्य की आड़ में विश्वविद्यालय किसी संबद्ध कॉलेज के प्रबंधन और रखरखाव को अपने हाथ में नहीं ले सकता है, चाहे वह निजी प्रबंधन या सरकार द्वारा चलाया जा रहा हो। 'सीखने की उन्नति और ज्ञान के प्रसार' की अभिव्यक्ति का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि विश्वविद्यालय को एक निजी कॉलेज के प्रबंधन के कर्तव्यों को अपने ऊपर लेने और कॉलेज के लिए कर्मचारियों को नियुक्त करने और छात्रों का चयन करने के लिए सशक्त बनाया जा सके। एक संबद्ध निजी कॉलेज के अपराधी प्रबंधन से निपटते समय इसकी शक्ति के भीतर क्या है, यह 1974 के अध्यादेश XXI के खंड 22 में बताया गया है। किसी कॉलेज के कर्मचारियों की नियुक्ति प्रबंधन का प्राथमिक कार्य है और इसलिए, कोई भी नहीं, लेकिन प्रबंधन या इसके लिए कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति प्रिंसिपल की नियुक्ति को प्रभावित नहीं कर सकता है, चाहे वह अस्थायी उद्देश्य के लिए हो या स्थायी रूप से। इस प्रकार, विश्वविद्यालय के पास किसी निजी कॉलेज के प्रिंसिपल को नियुक्त करने की कोई शक्ति नहीं है जो उससे संबद्ध है।

(पैरा 25, 27 and 30).

अभिनिर्धारित *:*

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 की उप-धारा (1) के अवलोकन से पता चलता है कि जिला मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को केवल दो प्रकार के निर्देश दे सकता है: (1) एक निश्चित अधिनियम से दूर रहना और (2) अपने कब्जे में या अपने प्रबंधन के तहत कुछ संपत्ति के संबंध में कुछ आदेश प्राप्त करना। संहिता की धारा 144 के प्रावधानों का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि जिला मजिस्ट्रेट स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति को कॉलेज और उसके परिसर और परिसंपत्तियों के पूरे प्रबंधन और कॉलेज को चलाने के कर्तव्य को संभालने के लिए अधिकृत

कर सकता है, जिसके बारे में कोई विवाद मौजूद था जिससे शांति भंग होने या सार्वजनिक अशांति होने की संभावना थी। इस प्रकार जिला मजिस्ट्रेट के पास संहिता की धारा 144 के तहत किसी कॉलेज के प्रशासक को नियुक्त करने की कोई शक्ति नहीं है, जब इसके प्रबंधन के बारे में विवाद हों।

(पैरा 33 and 36).

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि निम्नलिखित राहत दी जा सकती है: -

(क) *यह निधि पत्र जारी किया जाए कि रजिस्ट्रार श्री एसएस बाली, उपमंडल अधिकारी (सिविल), कैथल, थाना हाउस अधिकारी, थाना सिटी कैथल को निर्देश दिया जाए कि याचिकाकर्ताओं को उनकी कक्षाओं में भाग लेने से न रोका जाए;*

(ख) *प्रतिवादियों के अभिलेखों को मांगते हुए एक रिट पत्र जारी किया जाए और अभिलेख के अवलोकन के पश्चात् यह घोषित किया जाए कि सफल अभ्यथयों की सूची में से याचिकाकर्ताओं के नामों को रद्द करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है तो उसे रद्द करने का आदेश दिया जाए;*

(ग) *प्रतिवादी को एक उपयुक्त निदेश जारी किया जाए कि वह याचिकाकर्ताओं को इस संस्थान, जिसके लिए उन्हें विधिवत नामांकित किया गया था और वैध रसीदें जारी की गई थीं, के पूर्ण विकसित छात्रों के रूप में अपनी कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी जाए;*

(घ) *कॉलेज* प्राधिकारियों को यह निदेश देते हुए एक उपयुक्त आदेश जारी किया जाए कि वे याचिकाकर्ताओं और अनुलग्नक पी-4 में नामित अन्य छात्रों को कॉलेज के *नियमित छात्र मानें और उनकी शिक्षा के उचित संचालन के लिए सभी सुविधाएं और सुविधाएं प्रदान करें।*

(ङ) *कि कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा जारी विधिवत हस्ताक्षरित नोटिस को प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाए;*

(च) *उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों अध्याय V के अधीन नोटिस जारी करने का आदेश दिया जाए;*

(छ) *इस याचिका की लागत को भी अनुमति दी जाए।*

(ज) *इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादियों द्वारा अनंतिम रूप से अपनी कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने का आदेश दिया जाए ताकि*

याचिकाकर्ताओं के व्याख्यान कम न हों और प्रतिवादियों को भी किसी भी तरह से शिक्षा महाविद्यालय में याचिकाकर्ताओं के प्रवेश में हस्तक्षेप करने से रोका जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एसएम आशरी।

हरियाणा के वरिष्ठ उप महाधिवक्ता श्री डी.एस.लांबा और प्रतिवादी संख्या 3 और 5 की ओर से श्री आर.पी.दहया, एडवोकेट।

प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 4 के लिए जे एल गुप्ता, वकील।

निर्णय

न्यायमूर्ति **डी.एस. तेवतिया,** – (1) 1975 की दो रिट याचिकाओं संख्या 4751 और 5084 में, कानून और तथ्यों का सामान्य प्रश्न शामिल है और इसलिए, उन्हें निपटाने के लिए एक सामान्य आदेश प्रस्तावित है।.

(2) चूंकि दो रिट याचिकाओं में भौतिक तथ्य समान हैं, इसलिए 1975 के सिविल रिट नंबर 4751 में कथित तथ्य ध्यान देने के लिए पर्याप्त होंगे।

(3) कथित तथ्यों को इस प्रकार कहा जा सकता है: हरियाणा रूरल एजुकेशन सोसाइटी, कैथल (उत्तरदाता संख्या 6) (इसके बाद सोसाइटी के रूप में संदर्भित) के रूप में पंजीकृत एक सोसायटी कैथल में एक जाट हाई स्कूल के अलावा एक अन्य संस्थान का संचालन और प्रबंधन करती है, जिसे कैथल में ग्रामीण शिक्षा कॉलेज के रूप में जाना जाता है (इसके बाद कॉलेज के रूप में जाना जाता है)। उपरोक्त कॉलेज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से संबद्ध था और प्रासंगिक समय पर, एक श्री बीडी शाइदा, प्रतिवादी नंबर 4, इसके प्रिंसिपल थे। तथ्य यह है कि शैक्षणिक वर्ष 1975-1976 के लिए उपरोक्त कॉलेज में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे और कॉलेज की प्रबंध समिति ने प्रॉस्पेक्टस प्रकाशित किया था, जिसकी एक प्रति रिट याचिका के साथ अनुलग्नक पी 1 के रूप में संलग्न है, जिसमें प्रवेश के लिए योग्यता और आवेदन पत्र के अलावा अन्य प्रासंगिक जानकारी शामिल थी; प्रोस्पेक्टस के अलावा, सोसाइटी (प्रतिवादी संख्या 6) द्वारा संचालित कॉलेज सहित विभिन्न कॉलेजों में आयोजित बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश और साक्षात्कार की तारीख भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित की गई थी; उपरोक्त प्रॉस्पेक्टस में, अनुबंध पी 1 में, प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता कला, विज्ञान, कृषि और वाणिज्य में स्नातक होने का संकेत दिया गया था और 45 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त नहीं करने वाले उम्मीदवार और अनुसूचित जाति और अन्य निर्धारित श्रेणियों के मामले में 40 प्रतिशत से कम अंक नहीं थे, प्रवेश के लिए पात्र थे; बीएड पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित कुल सीटें 95 थीं; कि याचिकाकर्ताओं

ने, कई अन्य लोगों की तरह, उपरोक्त कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन किया; कि कॉलेज ने उनके प्रवेश फॉर्म की जांच के बाद, साक्षात्कार कार्ड जारी किए (ऐसे दो साक्षात्कार कार्ड रिट याचिका में अनुलग्नक पी. 2 और पी. 3 के रूप में संलग्न हैं); याचिकाकर्ताओं और ऐसे अन्य छात्रों, जिन्हें साक्षात्कार कार्ड जारी किए गए थे, को 28 जुलाई, 1975 को सुबह 8.00 बजे प्रिंसिपल, प्रतिवादी नंबर 4 की अध्यक्षता वाली चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना आवश्यक था; याचिकाकर्ता कुछ अन्य छात्रों के साथ निर्धारित समय पर 28 जुलाई, 1975 को चयन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और साक्षात्कार के बाद चयनित उम्मीदवारों की एक सूची, अनुलग्नक पी. 4, जिसमें याचिकाकर्ताओं के नाम थे, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किए गए थे; और यह कि उक्त सूची में प्रिंसिपल, प्रतिवादी नंबर 4, ने हालांकि, निम्नलिखित नोट संलग्न किया था:

स्थानीय प्रशासन द्वारा पैदा किए गए संकट को देखते हुए, उम्मीदवारों का चयन विशुद्ध रूप से उनके एमए/एमएससी और बीए/बीएससी परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर करने का निर्णय लिया गया है। अंतिम सूची नोटिस बोर्ड पर है और इसकी प्रतियां कॉलेज के हेड क्लर्क और अकाउंटेंट के पास देखी जा सकती हैं। 1 से 95 उम्मीदवारों को 3 दिनों के भीतर अपनी बकाया राशि जमा करनी होगी; ऐसा करने में विफल रहने पर प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवार अगले 2 दिनों में भर्ती होने के हकदार होंगे। नियमित कक्षाएं 4 अगस्त, 1975 से शुरू होंगी।

कि, चयन के तीन दिनों के भीतर फीस जमा करने के निर्देशों के अनुसरण में, याचिकाकर्ताओं ने अन्य लोगों के साथ कॉलेज के अधिकारियों के साथ कॉलेज की बकाया राशि जमा की और उन्हें रसीदें जारी की गईं, जिनकी मूल राशि अनुलग्नक पी. 5 से पी. 12 के रूप में रिट याचिका में संलग्न है; याचिकाकर्ता सभी मामलों में योग्य थे और याचिकाकर्ताओं से बेहतर अंक रखने वाले किसी भी छात्र को उम्मीदवारों में से खारिज नहीं किया गया था। जिन्होंने समय पर प्रवेश के लिए कॉलेज के अधिकारियों को आवेदन किया था; 4 अगस्त, 1975 को कॉलेज के उद्घाटन के दिन, जब याचिकाकर्ता कॉलेज में अपनी कक्षाओं में भाग लेने गए, तो उन्हें प्रतिवादी नंबर 2 श्री एसएस बाली द्वारा भाग लेने से रोक दिया गया, जिन्होंने खुद को कॉलेज का प्रभारी होने का दावा किया: याचिकाकर्ताओं और अन्य लोगों के विरोध के लिए कि उन्होंने अपने कॉलेज की बकाया राशि का भुगतान किया था और इस प्रकार वे अपनी कक्षाओं में भाग लेने के हकदार थे। श्री बाली ने कहा कि वह उस अवधि के दौरान कार्यालय द्वारा जारी रसीदों से बाध्य नहीं थे जब वह प्रिंसिपल नहीं थे; जब उन्होंने श्री बाली से अनुरोध किया कि उन्हें कॉलेज के प्राचार्य श्री बीडी शाइदा से मिलने की अनुमति दी जाए, तो उन्हें सूचित किया गया कि न तो श्री शाइदा और न ही उन्हें कॉलेज में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी और यदि उन्होंने कोई उपद्रव किया तो उन्हें पुलिस को सौंप दिया जाएगा जो पहले से ही

कॉलेज के बाहर तैनात थे; जब याचिकाकर्ता और अन्य छात्र अड़े रहे तो उन्हें श्री बाली द्वारा सूचित किया गया कि उनमें से केवल ऐसे छात्रों को कक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा जिनके पास उप-विभागीय अधिकारी (सिविल), कैथल की अनुमति होगी; जब याचिकाकर्ताओं ने उप-विभागीय अधिकारी (सिविल) के साथ साक्षात्कार की मांग की, तो उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और इसके बजाय उन्हें यह बताया कि वे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे; और इसके कारण याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादियों की कार्रवाई के खिलाफ अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया, जिसे उन्होंने याचिकाकर्ताओं को अन्य बातों के साथ-साथ कॉलेज में भाग लेने की अनुमति नहीं देने के लिए अवैध, अनुचित, अन्यायपूर्ण, असंवैधानिक और अवांछित करार दिया है, इस आधार पर (1) कि उन्हें नियमों और विनियमों के *साथ-साथ* संविधान में निहित शर्तों के अनुसार चयन समिति द्वारा विधिवत चुना गया था। प्रॉस्पेक्टस, अनुलग्नक पी.1, कॉलेज द्वारा जारी और (2) कि प्रवेश के लिए उनका चयन उत्तरदाताओं द्वारा उन्हें सुने बिना रद्द नहीं किया जा सकता है, जबकि कॉलेज द्वारा उनसे कॉलेज की बकाया राशि भी जमा की गई थी और उनका चयन विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर किया गया था।

(4) छह प्रतिवादियों में से पांच ने रिट याचिका में निहित आरोपों के जवाब में अपने अलग-अलग हलफनामे दायर किए हैं। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से, रजिस्ट्रार, श्री आरडी शर्मा द्वारा शपथ पत्र की शपथ ली गई है और इसमें लिया गया रुख यह है कि विश्वविद्यालय को वर्ष 1974 में किए गए प्रवेश के संबंध में कॉलेज को इस आशय की शिकायत मिली थी कि कॉलेज के अधिकारियों ने छात्रों से दान की आड़ में रिश्वत ली थी। यह कि आरोपों की जांच करने के लिए कुलपति द्वारा प्रतिनियुक्त कॉलेजों के एक निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट, अनुलग्नक आर 1 के *माध्यम से* उक्त आरोपों की पुष्टि की और इसलिए इस तरह के भ्रष्ट आचरण को रोकने के लिए, प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने सभी शिक्षा कॉलेजों को निर्देश जारी किए, जिसमें प्रवेश के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित की गई थी; कि 8 जुलाई, 1975 को, प्रतिवादी विश्वविद्यालय के कुलपति को कैथल से कई टेलीफोन कॉल प्राप्त हुए, जिसमें शिकायत की गई कि कॉलेज तब तक कोई आवेदन-पत्र जारी नहीं कर रहा है जब तक कि अग्रिम रूप से धन का भुगतान नहीं किया जाता है, जिसके बाद कुलपति ने शिकायत की जांच और रिपोर्ट के लिए प्रोफेसर डूल सिंह, डीन, वाणिज्य संकाय और वाणिज्य और प्रबंधन विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को नियुक्त किया। डूल सिंह ने रिपोर्ट के अनुलग्नक आर-2 के माध्यम से बताया कि कॉलेज के अध्यक्ष श्री एमएस ढुल ने उनसे कहा था कि कॉलेज ग्रामीण लोगों के लिए है और शहरी क्षेत्र में रहने वाले उम्मीदवार को एक भी सीट नहीं दी जाएगी; कि जब

उन्होंने प्रवेश के लिए आवेदन पत्र के लिए कार्यालय के प्रभारी से पूछा, उन्हें बताया गया कि यह 12 जुलाई, 1975 को दिया जाएगा, हालांकि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई, 1975 थी। प्रोफेसर डूल सिंह की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर, प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने दिनांक 8 जुलाई, 1975 को आदेश जारी किए, जिसमें कॉलेज के अध्यक्ष श्री एमएस ढुल को सभी प्रवेशों को रोकने और कॉलेज की प्रबंध समिति द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों को विश्वविद्यालय को अग्रेषित करने के लिए कहा गया और उसी आदेश द्वारा आवेदन-पत्र जमा करने की तारीख 22 जुलाई 1975तक बढ़ा दी गई।; 21 जुलाई, 1975 को कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक श्री एसए खान से कुलपति को एक डीओ पत्र, प्रति अनुलग्नक आर.4 प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया था कि श्री एमएस ढुल और उक्त कॉलेज के स्टाफ के अन्य सदस्य बीएड कक्षाओं में प्रवेश के लिए जानबूझकर पैसे की मांग करने का प्रयास कर रहे थे और वह दान के रूप में धन स्वीकार कर रहे थे और संभावित उम्मीदवारों को परेशान कर रहे थे। बी.एड. कक्षाओं में प्रवेश और श्री एस.ए. खान ने अपने डीओ पत्र में यह भी संकेत दिया कि वह श्री एमएस ढुल और अन्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं; श्री ढुल ने न तो आदेश, अनुलग्नक आर. 3 का कोई जवाब भेजा और न ही उसका अनुपालन किया, जिसके लिए 22 जुलाई, 1975 के संलग्नक आर.5 के एक पंजीकृत डाक द्वारा दूसरा पत्र लिखना आवश्यक हो गया, जिसे रिपोर्ट के साथ 'जानबूझकर मना कर दिया गया' प्राप्त हुआ था; जबकि इस बीच विश्वविद्यालय को शिकायतों की बाढ़ आ गई थी कि कॉलेज द्वारा प्रवेश के लिए संभावित उम्मीदवारों को आवेदन-पत्र की आपूर्ति नहीं की जा रही थी - ऐसी ही एक शिकायत अनुलग्नक आर 6 है; कॉलेज के अधिकारियों के इस आचरण के कारण विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि को 30 जुलाई, 1975 तक बढ़ाना आवश्यक हो गया था और इस आशय का एक टेलीग्राम भी 24 जुलाई, 1975 को कॉलेज के अधिकारियों को भेजा गया था। कॉलेज के अधिकारियों के इस असहयोगात्मक रवैये के कारण विश्वविद्यालय ने श्री आई.एस.दहिया, सहायक रजिस्ट्रार को कैथल जाने और सभी संबंधितों को सूचित करने के लिए नियुक्त किया; कि आवेदन-पत्र जमा करने की तारीख 30 जुलाई, 1975 तक बढ़ा दी गई थी और फॉर्म या तो कॉलेज के प्रिंसिपल के कार्यालय से या विश्वविद्यालय से प्राप्त किए जा सकते थे; इस तरह के नोटिस की एक प्रति उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कॉलेज के प्रमुख स्थानों पर चिपकाई थी, जिसमें नोटिस-बोर्ड (प्रति अनुलग्नक आर 8) और उसके बाद नोटिस, अनुलग्नक आर 9, इस आशय का पत्र भी प्रेस में प्रकाशित किया गया था - ऐसा ही एक नोटिस 27 जुलाई 1975 के अंक में ट्रिब्यून और वीर प्रताप में प्रकाशित किया गया था ; 26 जुलाई, 1975 को उत्तर देने वाले प्रतिवादी द्वारा श्री तारा चंद गुप्ता, डीलिंग असिस्टेंट को कैथल जाने और कॉलेज के प्रिंसिपल से प्रवेश फॉर्म लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था, जिन्होंने वहां पहुंचने पर कॉलेज परिसर को बंद पाया; 29 जुलाई, 1975 को प्रतिवादी

विश्वविद्यालय को कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक श्री एसए खान से एक और डीओ पत्र, अनुलग्नक आर 10 प्राप्त हुआ, जिसमें यह कहा गया था कि श्री एमएस ढुल अन्य सदस्यों के साथ जबरन वसूली कर रहे थे और बेईमानी से 2,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की भारी राशि उनके पक्ष में वितरित कर रहे थे; कॉलेज के प्रबंधन के सदस्यों को उस अवैध तरीके से उनके द्वारा प्राप्त धन के वितरण के संबंध में विभाजित किया गया था, जिसमें छात्र समुदाय के बीच अशांति पैदा करने की संभावना थी और इस प्रकार कानून और व्यवस्था के संबंध में गंभीर नतीजे थे, जिसके लिए उन्हें निवारक कार्रवाई करने की आवश्यकता थी; श्री खान ने महसूस किया कि निवारक कार्रवाई पर्याप्त नहीं थी और इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि एसडीओ (सिविल), कैथल को कॉलेज चलाने के लिए कहा जाए और उनकी सहायता के लिए विश्वविद्यालय द्वारा एक उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त किया जाए; श्री खान के उपर्युक्त सुझाव पर, श्री एसएस बाली , (प्रतिवादी संख्या 2) को कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने और उसमें प्रवेश को अंतिम रूप देने के लिए कैथल भेजा गया था; कुरुक्षेत्र के शिक्षा विभाग में रीडर डॉक्टर वाईपी अग्रवाल को चयन समिति में विश्वविद्यालय के नामित व्यक्ति के रूप में नामित किया गया था और जिला मजिस्ट्रेट को इस आशय के पत्र, अनुलग्नक आर. 11 द्वारा सूचित किया गया था; सहायक श्री आरसी गुप्ता ने एसडीओ (सिविल), कैथल की अनुमति से इस आशय के नोटिस-बोर्ड पर अनुलग्नक आर.12 लिखा था कि उक्त तिथि यानी 28 जुलाई, 1975 को कोई साक्षात्कार आयोजित नहीं किया जाएगा और इसलिए 28 जुलाई, 1975 को कोई साक्षात्कार आयोजित नहीं किया गया था; उस तारीख को प्रतिवादी नंबर 2 (श्री एसएस बाली) द्वारा यह अधिसूचित किया गया था कि चयन के लिए साक्षात्कार 5 अगस्त, 1975 को आयोजित किया जाएगा; और यह कि उपरोक्त तिथि पर साक्षात्कार एक चयन समिति द्वारा आयोजित किए गए थे जिसमें उत्तरदाता संख्या 2 और 3 शामिल थे। यह आगे उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता नंबर 1, जो साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुआ था, का चयन किया गया था और नियमित रूप से कक्षाओं में भाग ले रहा था; प्रतिवादी संख्या 4, यानी पूर्व प्राचार्य श्री बीडी शाइदा ने प्रतिवादी विश्वविद्यालय को दो पत्र भेजे, अनुलग्नक आर. 13 और आर. 14, जिसमें बताया गया कि किन परिस्थितियों में उन्हें बिना किसी साक्षात्कार के प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों को दिखाते हुए एक सूची पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था; यद्यपि उन्होंने एसडीओ (सिविल) से टेलीफोन कॉल प्राप्त करने पर जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया; और यह कि उनके द्वारा इस तरह की सूची पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद वह नरवाना गए, जहां से उन्होंने 28 जुलाई, 1975 को विश्वविद्यालय को अपना इस्तीफा पत्र भेजा।

(5) श्री बी.आर. आनंद (प्रतिवादी संख्या 3), उप-मंडल अधिकारी (नागरिक), कैथलयाचिका की विचारणीयता पर प्रारंभिक आपत्ति उठाने के अलावा, गुण-दोष के आधार पर, रजिस्ट्रार द्वारा अपने हलफनामे में कही गई बातों को दोहराने के अलावा, यह भी कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144, अनुलग्नक आर 3/1 के तहत आदेश पारित किए और उन्हें 30 जुलाई को कॉलेज का प्रशासन संभालने का निर्देश दिया। 1975 में एसडीओ (सिविल) के रूप में उनकी क्षमता में और उन्हें इस संबंध में सभी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि अध्यक्ष, कार्यकारी समिति के सदस्य, ग्रामीण शिक्षा महाविद्यालय, कैथल के प्राचार्य और प्रधान लिपिक को इस संबंध में उनके (एसडीओ) कर्तव्यों के निर्वहन में हस्तक्षेप करने से रोका जाना चाहिए। याचिकाकर्ता संख्या 2, हालांकि चयन समिति के समक्ष उपस्थित हुआ और गुण-दोष के आधार पर चुना गया, लेकिन उसने कॉलेज की बकाया राशि जमा नहीं की और न ही वह उसके बाद कॉलेज में आया और इस प्रकार प्रवेश के लिए उसका दावा जब्त हो गया और याचिकाकर्ता संख्या 3 और 4 ने न तो अपने आवेदन-पत्र जमा किए और न ही चयन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और इसलिए, कॉलेज में प्रवेश के लिए कोई दावा नहीं था; कॉलेज के प्राचार्य के कार्यालय से कुछ कागजात मिले और उनमें से एक में, अनुलग्नक आर 3/2, उन उम्मीदवारों के 95 नाम दिए गए थे, जिन्हें वर्ष 1975-1976 के लिए बीएड कक्षाओं में चुना गया था; और उपर्युक्त के अलावा, 28 जुलाई, 1975 को श्री बीडी शाइदा के हस्ताक्षर से एक अन्य कागजात, जो नोटिस का एक रूप था, भी वहां से पाया गया था और यह निम्नलिखित प्रभाव का था:

स्थानीय प्रशासन द्वारा पैदा किए गए संकट को देखते हुए उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से उनके एमए/एमएससी और बीए/बीएससी परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर करने का निर्णय लिया गया है। अंतिम सूची नोटिस-बोर्ड पर है और इसकी प्रतियां कॉलेज के हेड क्लर्क और एकाउंटेंट के पास देखी जा सकती हैं। 1 से 95 उम्मीदवारों को 3 दिनों के भीतर अपनी बकाया राशि जमा करनी होगी, ऐसा करने में विफल रहने पर प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवार अगले 2 दिनों में भर्ती होने के हकदार होंगे। 4 अगस्त, 1975 से नियमित कक्षाएं शुरू होंगी।

दिनांक: 28 जुलाई, 1975

(

(एसडी.).

प्रिंसिपल

कैथल

उक्त विवरणी में यह भी उल्लेख किया गया था कि प्रतिवादी संख्या 2 और 3 वाली चयन समिति ने 5 अगस्त, 1975 को योग्यता के आधार पर साक्षात्कार के बाद प्रवेश के लिए छात्रों का चयन किया और उनके नाम नोटिस-बोर्ड पर प्रदर्शित किए गए और यह अधिसूचित किया गया कि कॉलेज 11 अगस्त, 1975 को कार्य करना शुरू कर देगा और चयनित उम्मीदवारों को उस तारीख से पहले कॉलेज की बकाया राशि का भुगतान करना आवश्यक था।

(6) श्री बीडी शाइदा, प्रतिवादी संख्या 4 ने आरोपों के जवाब में अपने हलफनामे में कहा है कि गर्मी की छुट्टी के बाद कॉलेज 21 जुलाई, 1975 को फिर से खुल गया; उन्होंने 24 जुलाई, 1975 तक अपने कर्तव्यों का पालन किया और उसके बाद 25 और 26 जुलाई, 1975 के लिए छुट्टी ली; 27 जुलाई, 1975 को रविवार होने के कारण कॉलेज के प्रबंधक श्री राम सरन अंबाला में उनके निवास पर गए और उन्हें अपने (श्री राम सरन) साथ कैथल जाने के लिए कहा; श्री राम सरन उन्हें पहले कैथल के पुलिस स्टेशन ले गए, जहां कॉलेज के अध्यक्ष श्री एमएस ढुल को कैद कर लिया गया था; बाद में उन्होंने 28 जुलाई, 1975 को उम्मीदवारों के साक्षात्कार के लिए कॉलेज में उपस्थित होने का निर्देश दिया, इस तथ्य के बावजूद कि प्रतिवादी ने श्री ढुल को सूचित किया था कि जब फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई, 1975 तक बढ़ा दी गई है, तो साक्षात्कार आयोजित करना उचित नहीं होगा; 28 जुलाई, 1975 को सुबह 8.00 बजे कॉलेज पहुंचे जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।;कॉलेज के प्रबंधक ने उन्हें साक्षात्कार शुरू करने के लिए कहा; प्रबंधक को यह समझाने के उनके प्रयासों के बावजूद कि विश्वविद्यालय ने आवेदन-पत्र जमा करने की तारीख 30 जुलाई, 1975 तक बढ़ा दी है और विश्वविद्यालय से कोई आ सकता है, प्रबंधक ने साक्षात्कार शुरू करने पर जोर दिया; जब वह प्रबंधक से बात कर रहे थे, तब एसडीओ (सिविल), कैथल (प्रतिवादी नंबर 3) से एक टेलीफोन कॉल प्राप्त हुआ, जिसमें उन्हें (प्रतिवादी नंबर 4) उन्हें देखने की आवश्यकता थी; कि जब प्रतिवादी नंबर 4 ने कॉलेज से बाहर जाने का प्रयास किया, तो प्रबंधक द्वारा उसे साक्षात्कार आयोजित करने और एसडीओ (सिविल) के आदेश की अवज्ञा करने का आदेश दिया गया, जिसमें कहा गया था कि वह न तो एसडीओ (सिविल) के अधीन था और न ही विश्वविद्यालय के तहत; उक्त प्रबंधक ने उन्हें आगे बताया कि इन परिस्थितियों में साक्षात्कार संभव नहीं होगा और इसलिए, उन्हें बीएड कक्षाओं में भर्ती होने के लिए उम्मीदवारों की एक तैयार सूची पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है; उन्होंने दबाव में उपरोक्त सूची पर हस्ताक्षर किए; वास्तव में, कोई साक्षात्कार आयोजित नहीं किया गया था, क्योंकि किसी भी उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए अपने कार्यालय के अंदर नहीं बुलाया गया था; सूची पर हस्ताक्षर करने के बाद उन्होंने एसडीओ (सिविल) या किसी और से मिले बिना कैथल छोड़ दिया और नरवाना पहुंचे, जहां अपने बड़े भाई से परामर्श करने के बाद, उन्होंने उसी तारीख, यानी 28 जुलाई,

1975 को डाक द्वारा अपना इस्तीफा भेज दिया; इसके बाद वह उसी दिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के पास गए और शाम 5.30 बजे उनके घर पर उनसे मुलाकात की और उन्हें 28 जुलाई, 1975 को कॉलेज में जो कुछ हुआ था, उसके संबंध में एक रिपोर्ट, अनुलग्नक आर. 13 प्रस्तुत किया; उन्होंने 29 जुलाई, 1975 को कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक से उनके कार्यालय में मुलाकात की और उन्हें लिखित रूप से उपरोक्त तथ्यों की सूचना दी। उनके पास यह मानने का एक कारण था कि बीएड कक्षाओं में प्रवेश प्रबंधन द्वारा निष्पक्ष रूप से नहीं किया जा रहा था, क्योंकि विश्वविद्यालय के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया था और एक अफवाह चल रही थी कि प्रबंधन उस कक्षा में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों से दान ले रहा था; और चूंकि वह इस तरह के घोटाले में एक पक्ष नहीं बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 24 घंटे के नोटिस के साथ इस्तीफा दे दिया।

(7) श्री एसएस बाली, प्रतिवादी नंबर 2 ने केवल दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसमें उन उम्मीदवारों की सूची शामिल थी, जिन्हें उन्होंने और प्रतिवादी नंबर 3 ने प्रवेश के लिए चुना था, जो अनुलग्नक आर 2/1 था और उम्मीदवारों की एक सूची, अनुलग्नक आर 2/2 थी, जिसमें उन उम्मीदवारों के नाम दर्शाए गए थे जो उपरोक्त मेरिट सूची में थे और साथ ही उस सूची पर भी जो पहले कॉलेज के प्रबंधन द्वारा तैयार की गई थी; और उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों की एक प्रति, अनुलग्नक आर. 2/5, और नोटिस की एक प्रति, अनुलग्नक आर. 2/3 भी प्रस्तुत की, जिसके तहत आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई, 1975 तक बढ़ा दी गई थी।

(8) प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से, सोसाइटी ने अपने सचिव श्री शंकर लाल का एक हलफनामा रिकॉर्ड पर रखा है। उपरोक्त हलफनामे में प्रतिवादी नंबर 6 की ओर से ली गई दलील यह है कि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कैथल, वर्ष 1970 में प्रतिवादी सोसाइटी द्वारा शुरू किया गया था और इसे कानून के प्रावधानों के तहत पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ और बाद में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से विधिवत संबद्ध किया गया था; कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने उक्त कॉलेज के शासन और प्रशासन के उद्देश्य से पंजाब विश्वविद्यालय के विनियमों को अपनाया था; कि एक संबद्ध कॉलेज के प्रिंसिपल की शक्तियां निरंकुश हैं और उसके पास कॉलेज के आंतरिक प्रशासन से संबंधित सभी मामलों में अपने विवेक का उपयोग करने की पूरी शक्तियां हैं जिसमें छात्रों का प्रवेश भी शामिल है; यह कि प्रतिवादी सोसाइटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत एक स्वायत्त निकाय थी और प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 और 5 को कॉलेज के प्रशासन और छात्रों के प्रवेश सहित इसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं दी गई थी।;याचिकाकर्ताओं का विधिवत चयन किया गया था और इसलिए, वे इस संस्थान के छात्र थे; कि सदस्यों और प्रबंधन या शासी निकाय के बीच किसी भी तरह से कोई आंतरिक विवाद

नहीं था; कि कानून के प्रावधान जो विश्वविद्यालय की ओर से हस्तक्षेप की अनुमति देते हैं, सीमित हैं और केवल विश्वविद्यालय सिंडिकेट की सीमा तक हैं जो कुलपति को विश्वविद्यालय के प्रबंधन निकाय में एक प्रतिनिधि या प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए अधिकृत करते हैं। सिंडिकेट द्वारा निर्धारित अवधि के लिए कॉलेज और इस संबंध में पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर खंड 1, (1973 संस्करण) के पृष्ठ 164 पर नियम 11.2 का संदर्भ दिया जाए; कि याचिकाकर्ता बीएड कक्षा में प्रवेश के लिए पात्र थे; कि उन्हें योग्यता के आधार पर नियमित रूप से बुलाए गए साक्षात्कार में विधिवत चुना गया था और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप के लिए कोई अवसर नहीं था; उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदनों की संख्या कुल 158 थी और उनमें से याचिकाकर्ताओं सहित 95 उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर सख्ती से चुना गया था; कि बेचे गए आवेदन-प्रपत्रों की संख्या 200 थी; प्रतिवादी-सोसायटी याचिकाकर्ताओं के दावे को सभी मामलों में स्वीकार करती है और उन्हें कॉलेज के रोल पर छात्रों के रूप में मानती है और उत्तरदाताओं संख्या 1, 2, 3 और 5 के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप, यह इन छात्रों की जरूरतों को पूरा करने में अक्षम है; याचिकाकर्ताओं को अपनी पढ़ाई करने से रोकने में प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 और 5 की कार्रवाई कानून की उचित प्रक्रिया के बिना एक संबद्ध कॉलेज के *वास्तविक* छात्रों के निष्कासन और निष्कासन के समान है; कि कोई भी व्यक्ति, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया है, किसी भी तरह से संबद्ध कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में कानूनी रूप से कार्य नहीं कर सकता है - शासी निकाय ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने और हटाने के लिए एकमात्र सक्षम प्राधिकारी है; यदि प्रतिवादी-सोसायटी की प्रबंध समिति प्रतिवादी विश्वविद्यालय के किसी भी नियम और विनियमों के पालन के संबंध में चूक गई थी, तो सोसाइटी को केवल कैलेंडर में बताए गए तरीके से दंडित किया जा सकता है और कोई भी नियम या विनियमन या यहां तक कि किसी भी क़ानून का प्रावधान विश्वविद्यालय को प्रतिवादी-सोसायटी द्वारा संचालित संस्थान पर अपने प्रिंसिपल को सुपरइम्पोज करने के लिए अधिकृत नहीं करता है।

(9) प्रतिवादी-विश्वविद्यालय के विद्वान वकील श्री जेएल गुप्ता ने रिट याचिका की विचारणीयता पर तीन प्रारंभिक आपत्तियां उठाई हैं(1) याचिकाकर्ताओं को विचाराधीन कॉलेज में प्रवेश का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं है और इसलिए, न तो परमादेश की रिट के चरित्र का कोई उल्लेख किया जा सकता है और न ही प्रतिवादियों को कोई निर्देश जारी किया जा सकता है; (2) कि किसी निजी संस्थान, अर्थात् उस कॉलेज के विरुद्ध कोई रिट सक्षम नहीं है, जिसमें याचिकाकर्ता इस रिति याचिका के माध्यम से प्रवेश की मांग कर रहे हैं; और (3) कि रिट याचिका की सफलता की स्थिति में, याचिकाकर्ताओं की संख्या के बराबर छात्रों को उन छात्रों में से कॉलेज से विस्थापित करना होगा, जिन्हें उत्तरदाताओं

संख्या 2 और 3 द्वारा चुना गया था और इसलिए, ऐसे छात्र जिनके इस तरह विस्थापित होने की संभावना है, एक आवश्यक पक्ष हैं, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किए बिना, उनके नुकसान के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता था।.

(10) तीन प्रारंभिक आपत्तियों में से पहली आपत्तियों से निपटते हुए कि याचिकाकर्ताओं को प्रवेश लेने या निजी कॉलेज में प्रवेश पाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, यह देखा जाना चाहिए कि विचाराधीन कॉलेज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, प्रतिवादी नंबर 1 से संबद्ध है और यह स्वीकार किया गया मामला है कि कॉलेज राज्य सहायता प्राप्त कर रहा था (हरियाणा सरकार से पत्र X चिह्नित है)। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के खंड (2) के तहत, याचिकाकर्ताओं के राज्य-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के अधिकार को उनके विद्वान वकील द्वारा चुनौती दी गई है। इस खंड में लिखा है -

"राज्य द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा "

प्रतिवादी के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ताओं के उपरोक्त रुख का विरोध करते हुए आग्रह किया है कि संविधान के अनुच्छेद 29 का खंड (2) केवल उस स्थिति में लागू होता है जब उस खंड में परिकल्पित शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से इनकार कर दिया जाता है। अपनी दलील को विस्तार से बताते हुए, विद्वान वकील ने जोर देकर कहा कि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं को शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से इस आधार पर वंचित कर दिया गया है कि उन्हें प्रवेश के लिए विधिवत रूप से नहीं चुना गया था और संविधान के अनुच्छेद 29 के खंड (2) में उल्लिखित किसी भी निषिद्ध आधार पर नहीं।

(11) याचिकाकर्ताओं के वकील ने आग्रह किया है कि वास्तव में याचिकाकर्ताओं को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम, संविधियों, अध्यादेशों और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में विधिवत गठित चयन समिति द्वारा चुना गया था और आगे यह रुख अपनाया गया था कि किसी भी मामले में याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उनके आवेदनों पर विचार करने से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा विचाराधीन कॉलेज में नियुक्त प्रिंसिपल, भले ही, तर्क के लिए, यह स्वीकार किया गया था कि प्रतिवादी नंबर 2 के पास कॉलेज में प्रवेश के लिए छात्रों का चयन करने का अधिकार था। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री आशरी ने बॉम्बे राज्य बनाम *बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी और अन्य* 1955 एस.सी.आर 568 के फैसले से अपनी

उपरोक्त प्रस्तुति के लिए आधार मांगा है , *मद्रास राज्य* v. *श्रीमती चम्पकम दोराईराजन* 1961 एस.सी.आर.525 , *बंशीधर* बनाम *राजस्थान विश्वविद्यालय और एक अन्य* ए.आई.आर. 1963 राजस्थान 172 और *उमेश चन्द्र सिन्हा* बनाम *वी.एन. सिंह और अन्य*. ए.आई.आर. 1968 पटना 3। *बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी के मामले* (सुप्रा) में, सवाल यह था कि क्या वे छात्र, जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं थी, एंग्लो-इंडियन समुदाय द्वारा संचालित संस्थान में प्रवेश लेने के हकदार थे, जहां शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। परिपत्र के समर्थन में राज्य की ओर से तर्क दिया गया था, जिसके तहत ऐसे छात्र, जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं थी, को उस संस्थान में प्रवेश लेने से रोक दिया गया था, जहां शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था, यह था कि यह हिंदी के अध्ययन और सीखने को गति देने के लिए किया गया था, जिसे *भाषा* के रूप में मान्यता दी गई है। देश का प्रतिनिधित्व किया गया और यह भी आग्रह किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 29 को केवल अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा के लिए मौलिक अधिकारों के अध्याय में शामिल किया गया था। उच्चतम न्यायालय के माननिए न्यायमूर्ति ने इस तर्क को खारिज कर दिया और *श्रीमती चंपाकम दोराईरंजन के मामले* (उपर्युक्त) से निम्नलिखित टिप्पणी को मंजूरी दे दी -

"यह ध्यान दिया जाएगा कि खंड (1) नागरिकों के एक वर्ग की भाषा, लिपि या संस्कृति की रक्षा करता है, खंड (2) एक व्यक्तिगत नागरिक के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। खंड (2) में उल्लिखित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश पाने का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो एक नागरिक के पास एक नागरिक के रूप में है, न कि किसी समुदाय या नागरिकों के वर्ग के सदस्य के रूप में"।

बंशीधर के मामले (उपर्युक्त) में, पीठ की ओर माननिए न्यायमूर्ति शिंगल की निम्नलिखित टिप्पणियां शिक्षाप्रद हैं -

"जसवंत कॉलेज, जोधपुर एक सार्वजनिक संस्थान है जिसका रखरखाव सार्वजनिक लाभ के लिए राज्य के खजाने द्वारा किया जाता है। इसलिए, वे सभी जो पात्र हैं, इसमें प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं और किसी भी बाधा के अभाव में, यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। वे सभी जो अन्यथा अपेक्षित योग्यता को पूरा करते हैं और जब तक कॉलेज में रिक्ति है, उन्हें यह कहने का अधिकार है कि उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है और मनमाने और अवैध आधार पर कॉलेज में भर्ती होने से रोका नहीं जा सकता है। इस मामले में प्रवेश से इनकार करने का आदेश एक मौखिक आदेश है और यह दर्शाता है कि प्रवेश से इनकार कर दिया गया है क्योंकि, प्रिंसिपल के अनुसार, याचिकाकर्ता नियमों के तहत पात्र नहीं था। इसलिए, न्यायालय यह देखने का हकदार है कि क्या उपरोक्त आधार पर प्रवेश से इनकार करना उचित है।."

उमेश चंद्र सिन्हा के मामले (उपर्युक्त) में, जहां याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया सवाल यह था कि उसे अवैध आधार पर प्रवेश से वंचित कर दिया गया था, यह माना गया था कि आवेदक योग्यता के आधार पर अपने आवेदन पर विचार करने का हकदार था, भले ही वह प्रवेश का दावा नहीं कर सके। यह आगे माना गया कि भले ही ऐसे आवेदक हों जिनके पास याचिकाकर्ता की तुलना में अधिक अंक थे, याचिकाकर्ता को विश्वविद्यालय के अध्यादेश को भेदभावपूर्ण मानते हुए चुनौती देने के उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

(12) प्रतिवादी-विश्वविद्यालय के विद्वान वकील श्री जेएल गुप्ता ने *सतीश्वर सिंह बनाम मुख्य आयुक्त, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और अन्य* 1970 पीबी एल रिपोर्टर 76 *के अनुपात पर* अपनी दलील पर भरोसा किया । इस मामले में माननिए न्यायमूर्ति' तुली ने कहा था कि प्रवेश के लिए चुने जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है।. उस मामले में तथ्य यह था कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के वास्तविक निवासियों के लिए एक निश्चित चिकित्सा संस्थान में कुछ सीटें आरक्षित थीं । याचिकाकर्ता को उसके अंकों के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा चुना गया था, लेकिन बाद में उसका चयन रद्द कर दिया गया था जब यह पता चला कि उसने इस आशय का झूठा हलफनामा दायर किया था कि उसने प्रवेश के लिए अन्य मेडिकल कॉलेजों में आवेदन नहीं किया था। यह पता चला कि उन्होंने अन्य मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवेदन किया था और अपने अधिवास को चंडीगढ़ के अलावा अन्य होने का संकेत दिया था और यह इस पृष्ठभूमि के खिलाफ था कि विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के नामांकित व्यक्ति के रूप में मेडिकल कॉलेज में प्रवेश का कोई अधिकार नहीं है। न्यायालय के समक्ष प्रवेश के अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 पर टिकाने की मांग की गई थी और उस अनुच्छेद की भाषा का अर्थ लगाते हुए, यह टिप्पणी की गई थी कि प्रवेश के लिए चयनित होने का याचिकाकर्ता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं था। संविधान की धारा 29 इस बात से इनकार करती है कि छात्रों को उपर्युक्त खंड में परिकल्पित शैक्षिक संस्थान में प्रवेश के लिए विचार किए जाने का मौलिक अधिकार है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, श्री जेएल गुप्ता की यह दलील खारिज की जाती है कि याचिकाकर्ताओं को विचाराधीन कॉलेज में प्रवेश लेने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

(13) दूसरी प्रारंभिक आपत्ति, जिसमें कहा गया है कि रिट याचिका टिकाऊ नहीं है क्योंकि एक निजी कॉलेज के खिलाफ कोई रिट जारी नहीं की जा सकती है, समान रूप से त्रुटिपूर्ण है। सबसे पहले, रिट याचिका में मांगी गई राहत तीन प्रतिवादियों के खिलाफ निर्देशित है: प्रतिवादी नंबर 1, विश्वविद्यालय; प्रतिवादी नंबर 2, श्री एसएस बाली, जो विश्वविद्यालय (प्रतिवादी नंबर 1) द्वारा जारी एक आदेश के आधार पर खुद को कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में दावा

करते हैं; और प्रतिवादी नंबर 3, उप-विभागीय अधिकारी (नागरिक), कैथल। रिट याचिका में उल्लिखित याचिकाकर्ता के मामले के अनुसार, सभी तीन प्रतिवादियों के खिलाफ रिट जारी करना पूरी तरह से उचित है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्हें कॉलेज में प्रवेश के लिए विधिवत चुना गया था और उन्होंने अपनी फीस का भुगतान भी किया था। हालांकि, उन्हें प्रतिवादी नंबर 2, जो प्रिंसिपल होने का दावा करता है, और प्रतिवादी नंबर 3, जो कॉलेज का प्रशासक होने का दावा करता है, द्वारा अध्ययन करने और कक्षाओं में भाग लेने के अवसर से वंचित किया जा रहा था।.जहां तक कॉलेज प्रबंधन, जो याचिका के प्रतिवादी नंबर 6 का संबंध है, याचिकाकर्ताओं के दावे को स्वीकार करता है और एक रुख अपनाया है कि उन्हें संस्थान के रोल में विधिवत भर्ती कराया गया था और वे वहां अध्ययन करने के हकदार थे और प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 3 उक्त संस्थान में अध्ययन करने के उनके अधिकार में अवैध रूप से हस्तक्षेप कर रहे थे।

(14) भले ही, तर्क के लिए, यह स्वीकार किया जाता है कि अंतिम विश्लेषण में रिट प्रश्नगत कॉलेज के खिलाफ निर्देशित है, फिर भी, रिट उस कॉलेज के खिलाफ भी बनाए रखने योग्य है जो एक राज्य-सहायता प्राप्त संस्थान है और संविधान के अनुच्छेद 29 का खंड (2) एक छात्र को राज्य-सहायता प्राप्त संस्थान द्वारा भी प्रवेश के लिए अपने आवेदन पर विचार करने का अधिकार प्रदान करता है और आवश्यक निहितार्थ से, यह ऐसे राज्य-सहायता प्राप्त संस्थान पर एक संगत कर्तव्य डालता है कि वह प्रवेश के लिए एक आवेदक के दावे पर विचार करने से इनकार न करे। आवश्यक निहितार्थ से और लगभग उतनी ही निश्चितता के साथ, जितना दिन रात के बाद आता है, अधिकार प्रदान करने में उस व्यक्ति पर एक संगत कर्तव्य के कास्टिंग की परिकल्पना की गई है जिसके खिलाफ अधिकार दिया गया है और जब ऐसा व्यक्ति अवैध रूप से ऐसे व्यक्ति के अधिकार से इनकार करता है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय ऐसे व्यक्ति को रिट जारी करने के लिए सक्षम है, भले ही वह व्यक्ति एक निजी व्यक्ति हो। यह निर्णय लेने में क्या देखा जाना चाहिए कि क्या एक रिट किसी प्राधिकरण या किसी व्यक्ति के खिलाफ सक्षम है, यह है कि क्या कानून उस व्यक्ति पर एक दायित्व और याचिकाकर्ता पर एक संबंधित अधिकार डालता है। यदि कानून किसी निजी व्यक्ति पर ऐसा दायित्व डालता है और यदि ऐसा निजी व्यक्ति उस दायित्व को पूरा करने में अवैध रूप से कार्य करता है या अवैध रूप से उस दायित्व को पूरा करने से इनकार करता है, तो ऐसे निजी व्यक्ति को भी एक रिट जारी की जा सकती है। वर्तमान मामले में, संविधान के अनुच्छेद 29 के खंड (2) ने राज्य सहायता प्राप्त निजी संस्थान पर धर्म, नस्ल, जाति और भाषा के आधार पर संस्थान में आवेदक-छात्र को प्रवेश से इनकार नहीं करने का दायित्व डाला है। खंड (2) की भाषा में स्पष्ट रूप से प्रवेश के लिए आवेदक के दावे

पर उचित विचार करने की परिकल्पना की गई है और यदि किसी छात्र के प्रवेश के दावे पर विचार नहीं किया जाता है, तो वह कैसे दिखा सकता है कि उसे किन आधारों पर प्रवेश देने से इनकार किया गया था? बताए गए कारणों के लिए, हम मानते हैं कि हालांकि प्रतिवादी नं. 6, महाविद्यालय का प्रबंधन, फिर भी यदि अंतिम विश्लेषण में यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि महाविद्यालय के प्रबंधन के विरुद्ध राहत मांगी गई है, तो रिट इसके विरुद्ध विचारणीय है।

(15) जहां तक तीसरी प्रारंभिक आपत्ति का संबंध है कि रिट याचिका आवश्यक पक्षों के गैर-याचिकाकर्ता के लिए खारिज किए जाने के योग्य है, याचिकाकर्ताओं का रुख यह है कि उन्होंने उन छात्रों के खिलाफ कोई राहत नहीं मांगी है जिन्हें प्रतिवादी नं। 1, और, इसलिए ऐसे छात्र वर्तमान याचिका के लिए आवश्यक पक्षकार नहीं थे। याचिकाकर्ताओं की ओर से आगे यह तर्क दिया गया है कि भले ही, तर्क के लिए, यह स्वीकार किया जाता है कि याचिका की सफलता की स्थिति में, परिणाम यह होगा कि विश्वविद्यालय की चयन समिति द्वारा चयनित छात्रों को याचिकाकर्ताओं की संख्या के बराबर विस्थापित करना होगा, जब तक कि विश्वविद्यालय सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं करता है या उन्हें अन्य शैक्षणिक कॉलेजों में कहीं और समायोजित नहीं करता है, ऐसे छात्रों के नामों का पता नहीं लगाया जा सकता है, वही उत्तरदाताओं द्वारा रिटर्न में नहीं बताया गया है और इसलिए, उन छात्रों के नामों के संबंध में अनिश्चितता के कारण, जिनके याचिका के परिणाम से प्रभावित होने की संभावना हो सकती है, उन्हें वर्तमान याचिका में उत्तरदाताओं के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है।.

(16) हमारी राय है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा लिया गया रुख पूरी तरह से सही और उचित है, क्योंकि जब तक यह रिटर्न में यह ज्ञात नहीं किया जाता है कि याचिका की सफलता की स्थिति में प्रभावित होने वाले छात्र कौन होंगे, तब तक याचिकाकर्ता के लिए उन्हें प्रतिवादी के रूप में शामिल करना संभव नहीं हो सकता है। बताए गए कारणों के लिए, उत्तरदाताओं द्वारा उठाई गई इस प्रारंभिक आपत्ति में भी कोई योग्यता नहीं है।

(17) अब विचार के लिए जो प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या जब महाविद्यालय का प्रबंधन न केवल याचिकाकर्ताओं के प्रवेश के लिए विधिवत चयन किए जाने के संबंध में और साथ ही महाविद्यालय के देय राशि का भुगतान करने के संबंध में याचिकाकर्ताओं के रुख को पूरी तरह से स्वीकार करता है, तो प्रत्यर्थी नं. 2 श्री एस एस . बाली ने दावा किया कि स्वयं को प्रत्यर्थी नं. 1 और श्री बी .आर . कैथल के अनुमंडल अधिकारी (सिविल) आनंद ने जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कॉलेज का प्रशासक नियुक्त किए जाने का दावा करते हुए दिनांक 29 जुलाई, 1975 के अपने आदेश को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पारित

किया, ताकि याचिकाकर्ताओं को कॉलेज में शामिल होने और अपनी पढ़ाई करने से रोका जा सके।

(18) इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम की आवश्यकताओं और इस संबंध में उसके तहत बनाई गई विधियों, अध्यादेशों और विनियमों का पालन करने के बाद कॉलेज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से संबद्ध था। यह भी विवाद में नहीं है कि 28 जुलाई, 1975 तक, प्रतिवादी संख्या 6 ने कानूनी रूप से उक्त कॉलेज के प्रबंधन का गठन किया। यह भी विवाद में नहीं है कि प्रबंधन में कोई भी बदलाव केवल प्रतिवादी नंबर 6, हरियाणा ग्रामीण शिक्षा सोसायटी, कैथल के उप-नियमों के अनुसार प्रभावित हो सकता है, जो एक पंजीकृत सोसायटी है। इस बात पर भी विवाद नहीं किया जा सकता है कि प्राचार्य सहित स्टाफ की नियुक्ति प्रबंधन का कार्य था न कि विश्वविद्यालय और सरकार सहित किसी बाहरी प्राधिकारी का, हालांकि प्राचार्य के पद के साथ-साथ अन्य स्टाफ के लिए शैक्षिक योग्यता विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जा सकती है। पक्षकारों का यह भी स्वीकार किया गया मामला है कि 28 जुलाई, 1975 को प्रारंभ में प्रवेश के लिए साक्षात्कार की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया था और उस दिन चयन समिति द्वारा उनके अंकों के आधार पर 95 छात्रों की एक सूची तैयार की गई थी, जिसकी अध्यक्षता प्राचार्य बीडी शाइदा ने की थी। प्रतिवादी नंबर 4, हालांकि छात्रों के साथ आमने-सामने आए बिना यानी चयनित छात्रों से कोई प्रश्न पूछे बिना।

(19) 28 जुलाई, 1975 तक सोसाइटी, प्रतिवादी संख्या 6, निर्विवाद रूप से, विचाराधीन कॉलेज को चलाने और इसके मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थी और विचाराधीन कॉलेज में प्रवेश के लिए छात्रों के चयन की व्यवस्था करने के लिए भी जिम्मेदार थी। हालांकि, प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 3 ने यह रुख अपनाया है कि 28 जुलाई, 1975 को किया गया चयन कानून की नजर में कोई चयन नहीं था क्योंकि छात्रों का वास्तव में साक्षात्कार नहीं किया गया था और प्रिंसिपल को 95 छात्रों की तैयार सूची पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था। लेकिन इस प्रश्न पर जाने से पहले कि 28 जुलाई, 1975 को किया गया चयन वैध था या अमान्य, इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को यह कहने का कोई *अधिकार* है कि कॉलेज में प्रवेश के लिए याचिकाकर्ताओं का चयन अवैध था और फिर उन्हें कॉलेज में अपनी पढ़ाई करने से रोका जा सकता है।

(20) इसलिए, प्रश्न उठता है (1) क्या श्री एसएस बाली, प्रतिवादी नंबर 2, कॉलेज के कानूनी रूप से नियुक्त प्रिंसिपल हैं, चाहे *तदर्थ* या स्थायी आधार पर और (2) क्या प्रतिवादी नंबर 3, उप-विभागीय अधिकारी (सिविल), कैथल, को प्रतिवादी नंबर 6 के स्थान पर कॉलेज का विधिवत प्रशासक नियुक्त किया गया है।

(21) श्री एसएस बाली, विश्वविद्यालय द्वारा पारित एक आदेश के अनुसार प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने के अपने अधिकार का पता लगाते हैं, जिसमें उन्हें कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया गया है। अत, यह देखा जाना चाहिए कि क्या विश्वविद्यालय के पास ऐसी कोई शक्ति है। प्रतिवादियों के वकील जेएल गुप्ता ने तर्क दिया कि विश्वविद्यालय को कार्य करने की शक्ति, जैसा कि उसने कार्य किया था, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 की उप-धाराओं (ए) और (के) से आती है, (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित)। अधिनियम की धारा 4 इन शर्तों में है -

4. विश्वविद्यालय निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात्:-

(क) अधिगम की ऐसी शाखाओं में अनुसंधान और अनुदेश प्रदान करना, जो विश्वविद्यालय उपयुक्त समझे और ऐसे कदम उठाना, जो वह अधिगम की उन्नति और ज्ञान के प्रसार के लिए आवश्यक समझता है।;

(ख) परीक्षाओं का आयोजन करना और व्यक्तियों को ऐसी डिग्री, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक भेद या उपाधियां प्रदान करना जो संविधियों, अध्यादेशों या विनियमों में निर्धारित किए जा सकते हैं।;

(ग) अनुमोदित व्यक्तियों को मानद उपाधियाँ या अन्य सम्मान प्रदान करना संविधियों में उल्लिखित तरीके से;
(d) पुरस्कार, पदक, शोध छात्र, प्रदर्शनियों और फॉलोशिप स्थापित करने के लिए;

(घ) सरकार से उपहार, दान, लाभ प्राप्त करना और हस्तांतरणकर्ताओं, दाताओं, वसीयतकर्ताओं से उपहार, दान और चल या अचल संपत्ति का हस्तांतरण प्राप्त करना, जैसा भी मामला हो।;

(ड) प्रोफेसरशिप, रीडरशिप, लेक्चररशिप, फॉलोशिप और चेयर या किसी भी विवरण के पदों पर व्यक्तियों को स्थापित करना और नियुक्त करना;

(च) शिक्षकों, विद्वानों और प्रोफेसरों के आदान-प्रदान के माध्यम से भारत और विदेशों में शैक्षिक और अन्य संस्थानों के साथ सहयोग करना, जो विश्वविद्यालय के समान उद्देश्य रखते हैं, जो उनके सामान्य उद्देश्यों के लिए अनुकूल हो सकते हैं।;

(छ) ऐसे सभी कार्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आकस्मिक या सहायक हो सकते हैं।;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास और अनुशासन का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और उनके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए व्यवस्था करना;

(झ) विश्वविद्यालय से संबंधित या उसमें निहित किसी भी संपत्ति के साथ इस तरह से व्यवहार करना कि विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त समझे।;

() धारा 3-क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित कॉलेजों को बनाए रखना या, उस धारा की उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन, विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित नहीं बल्कि उक्त क्षेत्र के भीतर स्थित कॉलेजों को मान्यता देना और ऐसी मान्यता वापस लेना; और

(ट) संविधियों, अध्यादेशों या विनियमों को तैयार करना और उपर्युक्त सभी या किन्हीं उद्देश्यों के लिए उन्हें बदलना, संशोधित करना या रद्द करना.

(22) श्री जेएल गुप्ता ने आगे हमें अधिनियम से जुड़ी अनुसूची-I की संविधि 4 के उपखंड (iv) द्वारा परिकल्पित आपातकाल में कार्य करने की कुलपति की शक्ति का उल्लेख किया है, जो निम्नलिखित शर्तों में है::–

"उपा-कुलपति(कुलपति) की राय में, एक आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके लिए आवश्यक है कि तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए, 'उप-कुलपति' (कुलपति) ऐसी कार्रवाई करेंगे जो उन्हें आवश्यक लगता है और प्राधिकरण की अगली सफल बैठक में पुष्टि के लिए इसकी रिपोर्ट करेंगे, जो सामान्य रूप से इस मामले से निपटेगी"।

(23) श्री जेएल गुप्ता ने अधिनियम की धारा 4 के उपर्युक्त प्रावधानों और अनुसूची-I के उपबंधों के आधार पर यह रुख अपनाया है कि यदि विश्वविद्यालय को सीखने की उन्नति और ज्ञान के प्रसार के लिए आवश्यक समझा जाता है, तो वह प्राचार्य सहित संबद्ध कॉलेज के कर्मचारियों की नियुक्ति करने का कदम उठाने की सीमा तक जा सकता है। इसमें प्रवेश के लिए छात्रों का चयन करें और उन्हें निर्देश देने की व्यवस्था करें।.

(24) श्री जे.एल. गुप्ता ने 3 जनवरी, 1974 को कार्यकारी परिषद द्वारा पारित और अनुमोदित अध्यादेश XXI के खंड 22 के आधार पर तर्क दिया कि यदि विश्वविद्यालय संबद्ध कॉलेज के छात्र को विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए स्वीकार करने से इनकार कर सकता है, यदि उक्त कॉलेज अधिनियम और संविधियों या अध्यादेशों या विनियमों की आवश्यकताओं का पालन नहीं कर रहा है, इसके तहत बनाए गए और इसके द्वारा या इसकी ओर से जारी किए गए कोई अनुदेश, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि इससे कम एक मामूली सजा, यानी केवल

छात्रों को कॉलेज में अपनी पढ़ाई जारी रखने से इनकार करना, विश्वविद्यालय द्वारा विचाराधीन छात्रों पर नहीं लगाया जा सकता है?

*अध्यादेश XXI का खंड 22 निम्नलिखित शब्दों में है -

"यदि किसी भी समय कार्यकारी परिषद यह पाती है कि कोई कॉलेज विश्वविद्यालय के अधिनियम, संविधियों, अध्यादेशों या विनियमों की आवश्यकताओं या उसके द्वारा या उसकी ओर से जारी किसी भी निर्देश का पालन नहीं कर रहा है, तो कार्यकारी परिषद के पास निम्नलिखित दंडों में से कोई एक या अधिक लगाने का अधिकार होगा: -

(1) संबंधित कॉलेज के छात्रों को विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा;

(2) कॉलेज के कर्मचारियों को विश्वविद्यालय के काम जैसे परीक्षकों, परीक्षा केंद्रों के अधीक्षकों आदि के रूप में नियुक्ति से वंचित किया जाएगा;

(3) संबंधित प्रधानाचार्य या शिक्षक को विश्वविद्यालय निकाय में निर्वाचन या नामांकन प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा या उसका नाम विश्वविद्यालय निकायों के सदस्यों की सूची से हटा दिया जाएगा;

(4) कॉलेज को दी गई मान्यता आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से वापस ले ली जाए।

चूंकि, अध्यादेश XXI के खंड 22 के अलावा, जिस पर श्री जेएल गुप्ता ने भरोसा किया है, उक्त अध्यादेश के कुछ अन्य खंडों का भी मामले पर असर पड़ता है, इसलिए ये भी नोटिस के योग्य हैं। ये इस प्रकार हैं -

1. विश्वविद्यालय अपने विशेषाधिकारों में प्रवेश के लिए ऐसे कॉलेजों को मान्यता देगा जो समय-समय पर कार्यकारी परिषद द्वारा तय किए जा सकते हैं।

"2. मान्यता के लिए आवेदन करने वाला कॉलेज इस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट 1) में रजिस्ट्रार को आवेदन पत्र भेजेगा और कार्यकारी परिषद को संतुष्ट करेगा: -

(क) कि महाविद्यालय में एक नियमित रूप से गठित शासी निकाय होगा। (यह शर्त सरकार द्वारा बनाए गए कॉलेजों के मामले में लागू नहीं होगी)

(ख) शिक्षण स्टाफ की अर्हताएं, उनके वेतन-ग्रेड और उनके कार्यकाल को अभिशासित करने वाली शर्तें ऐसी हैं जो कॉलेज द्वारा शुरू किए जाने वाले शिक्षा पाठ्यक्रमों का कुशल संचालन सुनिश्चित करती हैं;

(ग) जिन भवनों में महाविद्यालय स्थित है, वे उपयुक्त हैं और यह उपबंध विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप, अपने माता-पिता या अभिभावकों के साथ न रहने वाले विद्याथयों के निवास के लिए, महाविद्यालय में या महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित आवासों के लिए और विद्याथयों के पर्यवेक्षण और शारीरिक कल्याण के लिए किया जाएगा;

(घ) पुस्तकालय के लिए प्रावधान किया गया है या किया जाएगा;

(ङ) जहां प्रायोगिक विज्ञान की किसी शाखा में मान्यता मांगी गई है, वहां विज्ञान की उस शाखा में उचित रूप से सुसज्जित प्रयोगशाला या संग्रहालय में अनुदेश प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप व्यवस्था की गई है या की जाएगी;

(च) कि जहाँ तक परिस्थितियाँ अनुमति दें, महाविद्यालय के प्रमुख और शिक्षण स्टाफ के कुछ सदस्यों के निवास स्थान के लिए या उसके आस-पास या विद्याथयों के निवास के लिए उपबंध किए गए स्थान के लिए उचित उपबंध किए जाएंगे;

(छ) कॉलेज के वित्तीय संसाधन ऐसे हैं कि इसके निरंतर रखरखाव के लिए उचित प्रावधान किए जा सकें;

(ज) कि उसी पड़ोस के अन्य कॉलेजों द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कॉलेज की मान्यता शिक्षा के हितों के लिए हानिकारक नहीं होगी; और

(झ) छात्रों द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस (यदि कोई हो) निर्धारित करने वाले कॉलेज के नियम इस प्रकार नहीं बनाए गए हैं कि उसी पड़ोस में किसी मौजूदा कॉलेज के साथ ऐसी प्रतिस्पर्धा को शामिल किया जाए जो शिक्षा के हितों के लिए हानिकारक हो।

आवेदन में यह आश्वासन भी होगा कि कॉलेज को मान्यता दिए जाने के बाद प्रबंधन के किसी भी हस्तांतरण और शिक्षण स्टाफ में सभी परिवर्तनों को तुरंत कुलपति को सूचित किया जाएगा और संस्थान समय-समय पर किए गए विश्वविद्यालय के प्रावधानों का ईमानदारी से पालन करेगा।

3 to 6–******

7. यदि कोई कॉलेज शैक्षणिक वर्ष के दौरान कक्षाएं शुरू करने में विफल रहता है, जिसके लिए अनुमति दी गई है, तो संबंधित पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) के लिए मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

"8. एक कॉलेज, कार्यकारी परिषद की पूर्व अनुमति के बिना, अध्ययन के पाठ्यक्रम (ओं) में निर्देश को निलंबित नहीं कर सकता है जिसके लिए वह पढ़ाने के लिए अधिकृत है।

9. *****

10. *****

11. प्रत्येक कॉलेज ऐसी रिपोर्ट, विवरणी और अन्य जानकारी भी प्रस्तुत करेगा जो कार्यकारी परिषद को समय-समय पर आवश्यकता हो ताकि वह कॉलेज की दक्षता का न्याय कर सके।

12. प्रत्येक मान्यता प्राप्त कॉलेज का प्राचार्य प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त से पहले रजिस्ट्रार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें निम्नलिखित दर्शाया गया है: -

(क) प्रबंधन में क्या परिवर्तन हुए हैं;

(ब) (i) शिक्षण स्टाफ और नए सदस्यों की योग्यता में परिवर्तन (ii) अन्य स्टाफ;

(ग) छात्रों की संख्या और वितरण;

(घ) पिछले वित्तीय वर्ष की आय और व्यय क्या है;

(ङ) परीक्षाओं के परिणाम;

(च) छात्रवृत्तियां;

(छ) पुस्तकालय की स्थिति; और

(ज) कॉलेज के छात्रावास में छात्रों की संख्या।

13. प्रत्येक मान्यता प्राप्त कॉलेज द्वारा निम्नलिखित रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर कुलपति द्वारा नामित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए: -

(1) प्रवेश और निकासी का एक रजिस्टर। रजिस्टर प्रत्येक छात्र के मामले में, प्रवेश की तारीख, जन्म तिथि, जन्म-स्थान का नाम, माता-पिता, कॉलेज परीक्षाओं में उपस्थिति और ऐसी परीक्षाओं के परिणाम, विश्वविद्यालय के करियर का रिकॉर्ड और नाम वापस लेने की तारीख देगा।

(2) व्याख्यानों में छात्रों की दैनिक उपस्थिति के रजिस्टर।

(3) फीस का एक रजिस्टर।

(4) एक समय-सारणी।

14. कार्यकारी परिषद प्रत्येक मान्यता प्राप्त कॉलेज का समय-समय पर उसके द्वारा अधिकृत एक या अधिक सक्षम व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण कराएगी

परन्तु ऐसे महाविद्यालय का सामान्यतः प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार और अन्य समय में निरीक्षण किया जाएगा जहाँ कार्यकारी परिषद की राय में ऐसा निरीक्षण आवश्यक हो।

15 to 22 *****

23. जहां कार्यकारी परिषद किसी कॉलेज की मान्यता को पूरी तरह से या आंशिक रूप से वापस लेने का प्रस्ताव करती है, कार्यकारी परिषद संबंधित कॉलेज के प्रमुख को एक नोटिस भेजेगी, जिसमें उन आधारों को बताया जाएगा जिन पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव है, इस संकेत के साथ कि कॉलेज की ओर से लिखित में प्रस्तुत कोई अभ्यावेदन, एक विशिष्ट अवधि के भीतर, कार्यकारी परिषद द्वारा विचार किया जाएगा। कार्यपालिका द्वारा आवश्यक समझे जाने पर इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

24. अभ्यावेदन प्राप्त होने पर या खंड 23 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर, कार्यकारी परिषद प्रस्ताव की सूचना, कथन और अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करेगी और ऐसा आदेश देगी जो परिस्थितियों की आवश्यकता हो।

25. जहां, खंड 24 के तहत किए गए आदेश द्वारा, मान्यता द्वारा प्रदत्त अधिकारों को पूरी तरह से या आंशिक रूप से वापस ले लिया जाता है, तो इस तरह की वापसी का आधार आदेश में बताया जाएगा और संबंधित कॉलेज के प्रमुख को सूचित किया जाएगा।

(25) अब इस विवाद से निपटते हुए कि विश्वविद्यालय को जो कुछ भी किया है उसे करने की शक्ति अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (ए) और (के) से आती है, यह देखा जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 4 विश्वविद्यालय द्वारा की जा सकने वाली गतिविधि के

दायरे और दायरे को इंगित करती है। सीखने की उन्नति और ज्ञान का प्रसार, निश्चित रूप से, किसी भी विश्वविद्यालय का मूल उद्देश्य है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इसका मतलब यह है कि शक्ति या कर्तव्य की आड़ में विश्वविद्यालय एक संबद्ध कॉलेज के प्रबंधन और रखरखाव को संभाल सकता है, चाहे वह निजी प्रबंधन या सरकार द्वारा चलाया जा रहा हो? यदि शक्ति को इतना व्यापक माना जा सकता है, तो भले ही कोई निजी कॉलेज विश्वविद्यालय से संबद्ध होने की इच्छा न रखता हो, फिर भी यह ऐसे निजी संस्थान की संबद्धता को मजबूर कर सकता है।

(26) बेशक, न तो अधिनियम की धारा 4 से पहले या बाद में अधिनियम के प्रावधानों में और न ही किसी विधि, अध्यादेश या विनियमों में, यह परिकल्पना की गई है कि विश्वविद्यालय *अपने* प्रबंधन की इच्छा के खिलाफ भी एक निजी कॉलेज को संबद्ध कर सकता है। इसके विपरीत, जैसा कि अध्यादेश XXI के विभिन्न खंड पहले ही पुन: प्रस्तुत किए गए हैं, यह दर्शाता है कि विश्वविद्यालय एक निजी कॉलेज के प्रबंधन द्वारा किए गए आवेदन पर संबद्धता स्वीकार करता है और इस बात से संतुष्ट होने पर कि अध्यादेश XXI में संबद्धता के लिए परिकल्पित आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है और, आवश्यक निहितार्थ द्वारा, विश्वविद्यालय की ओर से *स्वत: कार्रवाई* से इनकार करता है , एक निजी कॉलेज को संबद्ध करने के लिए।

(27(हमारे विचार में, 'सीखने की उन्नति और ज्ञान के प्रसार' की अभिव्यक्ति का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि विश्वविद्यालय को एक निजी कॉलेज के प्रबंधन के कर्तव्यों को लेने और कॉलेज के लिए कर्मचारियों को नियुक्त करने और छात्रों का चयन करने के लिए सशक्त बनाया जा सके। संबद्ध निजी कॉलेज के अपराधी प्रबंधन से निपटते समय इसकी शक्ति के भीतर क्या है, यह 1974 के अध्यादेश XXI के खंड 22 में बताया गया है। उपरोक्त खंड 22 के तहत शक्तियों के आधार पर भी, विश्वविद्यालय प्रबंधन को सुनवाई का अवसर दिए बिना उसमें उल्लिखित दंड नहीं लगा सकता था।

(28) विधियों की व्याख्या करने का सुस्थापित सिद्धांत यह है कि एक चीज के स्पष्ट उल्लेख का अर्थ है दूसरे का बहिष्करण (एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूसिया अल्टरनेटियस), या, दूसरे शब्दों में, जब अध्यादेश XXI के खंड 22 का विश्लेषण इस मैक्सिम के प्रकाश में किया जाता है, तो एकमात्र उचित निष्कर्ष यह है कि, इस खंड के तहत, विश्वविद्यालय के पास प्रबंधन का नियंत्रण ग्रहण करने या कॉलेज के प्रबंधन द्वारा किए गए छात्रों के चयन को रद्द करने का अधिकार नहीं है। स्वीकरण। यदि इरादा विश्वविद्यालय को अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से संबद्ध कॉलेज के प्रबंधन को संभालने की शक्ति देने का था, तो इस तरह के अधिकार को खंड में स्पष्ट रूप से बताया गया होगा।

(29) इसलिए, हमारा स्पष्ट रूप से विचार है कि विश्वविद्यालय, प्रतिवादी संख्या 1, के पास 10 जुलाई से आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को स्थगित करने के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में प्रबंधन की विफलता के कारण कॉलेज के प्रबंधन को संभालने की कोई शक्ति या अधिकार नहीं था। 1975 से 22 जुलाई, 1975 और फिर अंत में 30 जुलाई, 1975 तक और इसके परिणामस्वरूप साक्षात्कार की तिथि पूर्व निर्धारित तिथि अर्थात 28 जुलाई, 1975 से भविष्य की तारीख तक स्थगित कर दी गई।.

(30) प्रतिवादियों के वकील जेएल गुप्ता ने वैकल्पिक रूप से तर्क दिया कि प्रतिवादी नंबर 2 श्री एसएस बाली को प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त करने और कॉलेज में प्रवेश के लिए छात्रों के चयन को अंतिम रूप देने में विश्वविद्यालय की कार्रवाई कॉलेज के प्रबंधन को संभालने के समान नहीं है। हमें नहीं लगता कि विद्वान वकील द्वारा दी गई दलील में कम से कम दम है। निश्चित रूप से, कॉलेज के कर्मचारियों की नियुक्ति प्रबंधन का प्राथमिक कार्य है और इसलिए, प्रबंधन या इसके लिए कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति प्रिंसिपल की नियुक्ति को प्रभावित नहीं कर सकता है, चाहे वह अस्थायी उद्देश्य के लिए हो या स्थायी रूप से। इसलिए, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में श्री एसएस बाली को नियुक्त करने में प्रतिवादी-विश्वविद्यालय की कार्रवाई स्पष्ट रूप से अधिकार हीन थी।

(31) उत्तरदाताओं के कानूनी प्रतिनिधि श्री जेएल गुप्ता द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक तर्क की ओर मुड़ते हुए, यह सुझाव दिया जाता है कि यदि विश्वविद्यालय के पास विश्वविद्यालय परीक्षा में भाग लेने के लिए किसी छात्र को अस्वीकार करने का अधिकार है, तो तार्किक रूप से इसका अर्थ है कि विश्वविद्यालय के पास समान प्रकृति के निर्णय लेने की क्षमता है। दूसरे शब्दों में, यह सुझाव देता है कि विश्वविद्यालय कॉलेज में व्यक्तियों के प्रवेश और यदि भर्ती हो जाता है, तो क्या उन्हें कॉलेज में नामांकित रहना है, दोनों निर्धारित कर सकता है।.

(32) अफसोस की बात है कि एक बार फिर, विद्वान वकील दो अलग-अलग क्षेत्रों को जोड़ते हुए प्रतीत होते हैं- एक संबद्ध इकाई के रूप में विश्वविद्यालय के दायरे में आता है, जबकि दूसरा कॉलेज के प्रबंधन के पास है। संस्थान द्वारा पेश किए गए पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार, साथ ही एक छात्र को बर्खास्त करने की शक्ति, कॉलेज के प्रबंधन के पास है। दूसरी ओर, विश्वविद्यालय को इस संबंध में प्रशासनिक कार्रवाई करने का काम नहीं सौंपा गया है। इसकी भूमिका प्रवेश के लिए दिशानिर्देश, सिद्धांत और योग्यता स्थापित करना है। यदि कॉलेज का प्रबंधन इन दिशानिर्देशों से विचलित होता है, तो विश्वविद्यालय 1974 के अध्यादेश 21 के खंड 22 में उल्लिखित अपने अधिकार का उपयोग कर सकता है।

(33) जहां तक उप-विभागीय अधिकारी (सिविल), कैथल, प्रतिवादी संख्या 2 के कॉलेज के प्रशासक के रूप में कार्य करने के अधिकार का संबंध है, यह जिला मजिस्ट्रेट के दिनांक 29 जुलाई, 1975 के आदेश पर निर्भर करता है, जो उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए पारित किया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के प्रासंगिक भाग में लिखा है:-

> "144. (1) *उन मामलों में, जिनमें जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किए गए किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राय में इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है और तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है, वह मजिस्ट्रेट ऐसे लिखित आदेश द्वारा जिसमें मामले के तात्विक तथ्यों का कथन होगा और जिसकी तामील धारा 134 द्वारा उपबंधित रीति से कराई जाएगी, किसी व्यक्ति को कार्य-विशेष न करने या अपने कब्जे की या अपने प्रबंधाधीन किसी विशिष्ट संपत्ति की कोई विशिष्ट व्यवस्था करने का निदेश उस दशा में दे सकता है जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट समझता है कि ऐसे निदेश से यह संभाव्य है, या ऐसे निदेश की यह प्रवृत्ति है कि विधिपूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति का, या मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का, या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का, या बलवे या दंगे का निवारण हो जाएगा।*.
>
> (2) *इस धारा के अधीन आदेश, आपात की दशाओं में या उन दशाओं में जब परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस व्यक्ति पर, जिसके विरुद्ध वह आदेश निदिष्ट है, सूचना की तामील सम्यक् समय में करने की गुंजाइश न हो, एक पक्षीय रूप में पारित किया जा सकता है।*.
>
> (3) *इस धारा के अधीन आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति को, या किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को अथवा आम जनता को, जब वे किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में जाते रहते हैं या जाएं, निदिष्ट किया जा सकता है।*.
>
> (4) *इस धारा के अधीन कोई आदेश उस आदेश के दिए जाने की तारीख से दो मास से आगे प्रवृत्त न रहेगा :*
>
> *परंतु यदि राज्य सरकार मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का निवारण करने के लिए अथवा बलवे या किसी दंगे का निवारण करने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश उतनी अतिरिक्त अवधि के लिए, जितनी वह उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, प्रवृत्त रहेगा; किंतु वह अतिरिक्त अवधि उस तारीख*

से छह मास से अधिक की न होगी जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश ऐसे निदेश के अभाव में समाप्त हो गया होता।

(5) *****

(6) *****

(7) *****

सीआरपीसी की धारा 144 की उप-धारा (1) के अवलोकन से पता चलता है कि जिला मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को केवल दो प्रकार के निर्देश दे सकता है: (1) एक निश्चित अधिनियम से दूर रहना और (2) अपने कब्जे में या अपने प्रबंधन के तहत कुछ संपत्ति के संबंध में कुछ आदेश प्राप्त करना।.

(34) फिलहाल, आदेश में कही गई बातों को स्वीकार करते हुए, जिसके लिए इसे पारित करना आवश्यक था, यह सब सच है, यह देखा जाना चाहिए कि क्या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश पारित किया जा सकता है। आदेश का प्रचालनात्मक भाग निम्नलिखित शब्दों में है -

"जबकि मुझे यह प्रतीत हुआ है कि आपके पास ग्रामीण शिक्षा महाविद्यालय, कैथल, जिला कुरुक्सबेतरा का प्रबंधन है और बीएड पाठ्यक्रम के लिए कॉलेज में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों से निर्धारित शुल्क से अधिक धन की वसूली के लिए संदिग्ध साधनों को अपनाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।. प्रवेश फॉर्म केवल ऐसे उम्मीदवारों को प्रदान किए जाते हैं जो मांगे गए भुगतान करने की स्थिति में हैं और इतनी बड़ी संख्या में संभावित उम्मीदवारों, अन्यथा योग्य, को प्रवेश के लिए आवेदन करने के अवसर से वंचित कर दिया गया है। अध्यक्ष श्री महिंदर सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420/384 के तहत दिनांक 24 जुलाई, 1975 का मामला एफआईआर संख्या 166 पहले ही दर्ज किया जा चुका है, जिसकी अभी जांच चल रही है और उपर्युक्त कदाचार के कारण सदस्य विभाजित हैं और अवैध रूप से स्वीकार किए गए धन के वितरण पर विवाद है। जनता और छात्र समुदाय के बीच भी बहुत असंतोष है और यह सब सार्वजनिक शांति की गड़बड़ी या अशांति में होने की संभावना है।

और जबकि, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि तत्काल कार्रवाई के लिए ऊपर उल्लिखित पर्याप्त आधार हैं और कॉलेज प्रशासन के सुचारू कामकाज के लिए और सार्वजनिक शांति में खलल या अशांति को रोकने के लिए निर्देश आवश्यक हैं।

अब, इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

मैं

कुरुक्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट दीपक दास गुप्ता यह आदेश देते हैं कि कैथल के उप-मंडल मजिस्ट्रेट कॉलेज का प्रशासन करेंगे और इस संबंध में सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और आगे आपको इस संबंध में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में हस्तक्षेप करने से रोका जाता है।

आदेश के उपरोक्त ऑपरेटिव सेक्शन की जांच से पता चलता है कि जिला मजिस्ट्रेट ने इसके संचालन की देखरेख के लिए उप-विभागीय अधिकारी (सिविल), कैथल को कॉलेज के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त, आदेश में कहा गया है कि दस्तावेज में निर्दिष्ट व्यक्तियों को कॉलेज के प्रबंधन में उप-विभागीय अधिकारी (सिविल), कैथल द्वारा किए गए कार्यों में बाधा डालने से प्रतिबंधित किया गया है।.

(35) हमारे विचार में, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 की उपधारा (1) के शब्द, इसके अलावा किसी अन्य व्याख्या की अनुमति नहीं देते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट को केवल अपने आदेश में निर्दिष्ट व्यक्तियों को निर्देश देने के लिए अधिकृत किया गया था। आदेश में उल्लिखित आधारों के आधार पर इन कार्रवाइयों ने उस निर्देश को जारी करने को उचित ठहराया - विशेष रूप से, कॉलेज के संचालन से बचना, इसके वित्त का प्रबंधन करना, या, एक विकल्प के रूप में, प्रबंधन के कब्जे में संपत्ति के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों का पालन करना। यह आदेश में उल्लिखित कॉलेज प्रबंधन के सदस्यों के बीच विवाद से संबंधित था, जिसमें कॉलेज के लिए दान के रूप में छात्रों से अवैध राशि की कथित स्वीकृति शामिल थी।

(36) इस बात का कोई संकेत नहीं है कि कॉलेज परिसर, कर्मचारियों की नियुक्तियों, छात्र साक्षात्कार, या उनके शेड्यूलिंग के संबंध में प्रबंधन के भीतर कोई असहमति थी। निश्चित रूप से, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के प्रावधानों की यथोचित व्याख्या यह सुझाव देने के लिए नहीं की जा सकती है कि जिला मजिस्ट्रेट, या तो व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकरण के माध्यम से, विवादित संपत्ति का नियंत्रण जब्त करने का अधिकार था। इस मामले में, विवादित संपत्ति में कॉलेज का पूरा प्रबंधन शामिल है, जिसमें इसके परिसर, संपत्ति और कॉलेज के संचालन की जिम्मेदारी शामिल है। यह धारा 144 के तहत केवल तभी स्वीकार्य होगा जब कब्जे को लेकर विवाद हो जिसके परिणामस्वरूप शांति भंग होने या सार्वजनिक अशांति होने की संभावना हो। इस परिप्रेक्ष्य का समर्थन करते हुए कि जिला मजिस्ट्रेट के पास इस तरह के अधिकार का अभाव है, हम रूपन सिंह और अन्य बनाम सम्राट (एआईआर 1944 पटना 213।) के मामले में न्यायमूर्ति रूबेन द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं में सुदृढीकरण पाते हैं , एक ऐसा रुख जिसके साथ हम तहे दिल से सहमत हैं:

"सीआरपीसी की धारा 144 के अवलोकन पर, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है कि फसल काटने के लिए उप-निरीक्षक को विवेकाधिकार अधिकार क्षेत्र के बिना था। धारा 144 के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियां उचित परिस्थितियों में, किसी भी व्यक्ति को "एक निश्चित कार्य से दूर रहने या अपने कब्जे में या उसके प्रबंधन के तहत कुछ संपत्ति के साथ कुछ आदेश लेने के लिए" निर्देश तक विस्तारित करती हैं। यहां संपत्ति कब्जे में नहीं थी या पुलिस उप-निरीक्षक के प्रबंधन में नहीं थी, मजिस्ट्रेट के पास उसे उस संपत्ति के कब्जे में रखने और उसे फसल काटने का निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं था।

(37) चूंकि प्रबंधन का गठन करने वाले सदस्यों को केवल कॉलेज के प्रशासक के रूप में उप-विभागीय अधिकारी (सिविल), कैथल के कार्यों में हस्तक्षेप करने से बचने का निर्देश दिया गया था, जिनकी नियुक्ति स्वयं स्पष्ट रूप से अवैध थी, जैसा कि पहले से ही कहा गया था कि उप-विभागीय अधिकारी के कृत्यों और कार्यों में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया गया था, जो स्वयं अवैध और अनधिकृत थे। यह स्पष्ट रूप से जारी करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के अधिकार से परे था।

(38) प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से यह आग्रह किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की अवैधता को न तो रिट याचिका में चुनौती दी गई है और न ही रिट याचिका के प्रतिवादी के रूप में जिला मजिस्ट्रेट को पक्षकार बनाए बिना अदालत द्वारा इसे दूर किया जा सकता है। इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 3 के वकील श्री आरपी दहया ने उदित नारायण सिंह मालपहाड़िया बनाम *राजस्व बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य, बिहार और अन्य* ए.आई.आर. 1963 एस.सी. 786 मामले में माननिए न्यायमूर्ति सुभा राव की निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया :

"उप्रेषण की रिट में संक्षेप में न केवल ट्रिब्यूनल या प्राधिकरण जिसका आदेश रद्द करने की मांग की गई है, बल्कि जिन पार्टियों के पक्ष में उक्त आदेश जारी किया गया है, वे आवश्यक पक्ष हैं।

माननिए न्यायमूर्ति द्वारा प्रतिपादित प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है, लेकिन उपरोक्त अवलोकन का अनुपात केवल तभी आकर्षित होता है जब आदेश को रद्द करने की मांग की जाती है।. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं द्वारा आदेश को रद्द करने की मांग नहीं की गई है। हालांकि, तथ्य यह है कि आदेश को रद्द करने की मांग नहीं की गई है, अदालत को इसकी वैधता में जाने से नहीं रोक सकता है जब याचिका में एक पक्ष होने वाले व्यक्ति के कार्य की वैधता इस निष्कर्ष पर निर्भर करती है कि जिस आदेश पर ऐसा पक्ष कार्य करने की

अपनी शक्ति का पता लगाता है वह कानूनी है या अवैध। इस संबंध में, वरयाम सिंह बनाम *राज्य* 1972 पी.एल.आर. 687 के *रूप में रिपोर्ट किए गए एक आपराधिक मामले से एक उपमा पर वापस गिर सकता* है, जहां उच्च न्यायालय में यह प्रश्न उठा कि क्या ऐसे मामले में अपीलीय न्यायालय के लिए यह निष्कर्ष निकालना खुला है कि ऐसे बरी किए गए व्यक्तियों को बरी किए जाने के खिलाफ कोई सरकारी अपील नहीं है, कि, हालांकि वह इस तरह के बरी होने में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ऐसे व्यक्तियों या उनमें से कुछ को गलत तरीके से बरी कर दिया गया था और वास्तव में अपीलकर्ता के साथ मिलकर कथित कृत्य में भाग लिया था और इस आधार पर अपीलकर्ता को सही तरीके से दोषी ठहराया गया था। इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने, जिसमें मैंने भाग लिया और निर्णय प्रदान किया, गुलाब बनाम राज्य (ए.आई.आर. 1951 660) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय के अनुसार फैसला सुनाया। फैसले ने पुष्टि की कि अदालत के पास अपीलकर्ता के मामले का आकलन करते समय यह घोषित करने का अधिकार है कि सह-अभियुक्त को बरी करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कानूनी रूप से सही नहीं था। यद्यपि बरी किए जाने के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई थी और इसे पलटा नहीं जा सकता था, लेकिन अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के समर्थन से यह दृढ़ संकल्प किया जा सकता था कि सह-अभियुक्त वास्तव में दोषी थे।. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ताओं के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वे जिला मजिस्ट्रेट को रिट याचिका के प्रतिवादियों में से एक के रूप में शामिल करें। न ही उस मामले के लिए, उनके उद्देश्य के लिए इस रिट याचिका में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को सीधे लागू करना भी आवश्यक था। कॉलेज के प्रशासन को चलाने में कैथल के उप-विभागीय अधिकारी (सिविल) के कृत्य को चुनौती देना और उन्हें अवैध और बिना अधिकार के कॉलेज में शामिल होने से रोकना उनके लिए पर्याप्त था।.

(39) हालांकि, प्रतिवादियों के वकील ने तर्क दिया कि प्रतिवादियों और 2 के कृत्यों की वैधता को रिट याचिका में कुछ निर्दिष्ट आधारों पर चुनौती दी गई है और यह आधार कि एसडीओ (सिविल), प्रतिवादी नंबर 3 के पास कॉलेज के प्रशासक के रूप में कार्य करने का अधिकार नहीं है क्योंकि उन्हें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

(40) इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिका में उपरोक्त आशय का एक स्पष्ट आधार नहीं लिया गया है, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने सामान्य शब्दों में प्रतिवादियों के कृत्यों को अवैध और बिना अधिकार के बताया है। इसलिए एसडीओ (सिविल) और प्रतिवादी नंबर 2 श्री बाली पर भी यह दिखाने का दायित्व था कि उनके पास उनके तरीके से कार्य करने का कानूनी अधिकार

है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम नियम देते हैं कि न तो प्रतिवादी नंबर 2 के पास कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने का कोई कानूनी अधिकार था और न ही प्रतिवादी नंबर 3 के पास उक्त कॉलेज के प्रशासक के रूप में कार्य करने का ऐसा अधिकार था।

(41) एक बार ऐसा हो जाने के बाद, वे अपनी पूर्वोक्त क्षमता में कोई भी नहीं हैं जो कॉलेज में प्रवेश के लिए याचिकाकर्ताओं के चयन पर सवाल उठाते हैं या उन्हें कक्षाओं में शामिल होने से रोकते हैं, अगर कॉलेज का प्रबंधन संतुष्ट है कि याचिकाकर्ताओं को प्रवेश के लिए विधिवत चुना गया है। ऐसा कहते समय, हमें यह नहीं समझा जाना चाहिए कि विश्वविद्यालय को यह देखने के लिए रोक दिया गया है कि उसके द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए छात्रों की स्वीकृति का समय कब आता है कि क्या प्रबंधन अधिनियम, संविधि, अध्यादेश, विनियमों और विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार स्वयं का संचालन कर रहा है। यदि यह पाया जाता है कि कॉलेज प्रबंधन इस तरह से कार्य नहीं कर रहा है, तो यह उसके लिए खुला होगा कि वह उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है जैसा कि खंड (22) या अध्यादेश 21 में परिकल्पना की गई है।

(42) इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि प्रतिवादी नंबर 2 को प्रिंसिपल और प्रतिवादी नंबर 3 को कॉलेज के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के आदेश जारी करते समय हम एक पल के लिए भी विश्वविद्यालय, प्रतिवादी नंबर 1, या जिला मजिस्ट्रेट की ओर से किसी भी दुर्भावनापूर्ण इरादे का अनुमान नहीं लगाते हैं। हम यह भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि प्रबंधन के आचरण और उसके खिलाफ आरोपों की सच्चाई के बारे में धारणाएं अच्छी तरह से स्थापित हो सकती हैं और उनके कार्यों के पीछे का उद्देश्य अच्छी तरह से प्रशंसनीय हो सकता है, लेकिन अदालत किसी पार्टी के कार्य की वैधता पर विचार करते समय केवल इस बात से चिंतित है कि क्या कानून उस व्यक्ति को उस तरीके से कार्य करने की अनुमति देता है जो उसने किया है और यह नहीं कि क्या उद्देश्य ने प्रेरित किया था। जिस तरह से कार्य करने का अधिकार अच्छा या प्रशंसनीय था। यहां तक कि गैरकानूनी और डेस्पेराडो के मामले में, कानून उनके एकमुश्त परिसमापन की अनुमति नहीं देता है, हालांकि इसका उद्देश्य समाज को उनके हाथों उत्पीड़न से बचाने के प्रशंसनीय उद्देश्य को पूरा करना हो सकता है।.

(43) फैसले पर चर्चा करने से पहले, हम देख सकते हैं कि किसी भी प्रतिवादी ने याचिका में आरोपों पर विवाद नहीं किया है कि याचिकाकर्ताओं को उनके द्वारा प्राप्त अंकों के अनुसार और विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित पात्रता के मानदंडों के अनुसार योग्यता के आधार पर चुना गया था और न ही यह विवादित है कि याचिकाकर्ता 4 अगस्त को कॉलेज गए थे। 1975 में उन्हें कक्षाओं में शामिल होने के लिए कहा गया था और उन्हें श्री बाली, प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा ऐसा करने से रोका गया था, भले ही उन्होंने उन्हें बताया था कि उनके पास रसीदें हैं

और उन्होंने उचित चयन के बाद अपने कॉलेज के बकाया का भुगतान किया था; कि अंत में, जब याचिकाकर्ताओं ने कॉलेज में शामिल होने पर जोर दिया, तो उन्हें सूचित किया कि वह उन्हें एसडीओ (सिविल) से अनुमति मिलने के बाद ही प्रवेश देगा; और जब उन्होंने एसडीओ (सिविल) से संपर्क किया, तो उन्होंने उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया और उन्हें बताया कि उन्हें निवारण के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए।

(44) साक्षात्कार की वैधता को प्रतिवादियों द्वारा केवल इस आधार पर चुनौती दी गई है कि, वास्तव में, 28 जुलाई, 1975 को कोई उचित साक्षात्कार नहीं हुआ था, क्योंकि छात्रों को चयन समिति द्वारा नहीं बुलाया गया था और एक तैयार सूची को अपनाने के लिए मजबूर किया गया था। हालांकि, यह उनका मामला नहीं है कि चयनित उम्मीदवारों की सूची में शामिल उम्मीदवार या तो प्रवेश के लिए पात्र नहीं थे या चयन उनके द्वारा प्राप्त अंकों के अनुसार सख्ती से नहीं किया गया था।

(45)28 जुलाई, 1975 को किए गए चयन की वैधता को चुनौती देने के लिए इस्तेमाल किया गया दूसरा तर्क यह था कि विश्वविद्यालय ने पहले ही आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा 30 जुलाई, 1975 तक बढ़ा दी थी, जिसका अर्थ है कि कॉलेज का प्रबंधन 28 जुलाई, 1975 को साक्षात्कार आयोजित नहीं कर सकता था, और चयन समिति, जिसने साक्षात्कार आयोजित किया और 28 जुलाई को सूची को अंतिम रूप दिया, 1975, अपर्याप्त था क्योंकि न तो विश्वविद्यालय और न ही सरकार के नामांकित व्यक्ति साक्षात्कार के दौरान उपस्थित थे या चयनित उम्मीदवारों की सूची पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।

(46) कहने की जरूरत नहीं है कि ये ऐसे मामले हैं जिनके बारे में कॉलेज प्रबंधन को प्रासंगिक समय पर विश्वविद्यालय को संतुष्ट करना होगा और यदि विश्वविद्यालय, प्रतिवादी नंबर 1, इस विचार पर कायम है कि कॉलेज प्रबंधन विश्वविद्यालय के निर्देशों का उल्लंघन कर रहा था या अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा था, अध्यादेश, नियम और विनियम या संबद्धता की शर्तें, कानून के अनुसार, प्रबंधन को उचित अवसर देने के बाद कोई भी उचित कार्रवाई करने के लिए उसके लिए खुला होगा।.

(47) परिणाम में, हम लागत के साथ याचिकाओं की अनुमति देते हैं और प्रतिवादियों, विशेष रूप से उत्तरदाताओं संख्या 1, 2 और 3 की सराहना करते हैं, ताकि याचिकाकर्ताओं को कॉलेज में शामिल होने और कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति मिल सके।

न्यायमूर्ति प्रीतम सिंह पट्टर,

एन.के.एस.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सचिन सिंघल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हिसार , हरियाणा